



हिन्दी में प्रकाशित होने वाला सबसे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र 'सद्भावना टुडे' में विज्ञापन के लिए संपर्क करें :-
011-43678240
E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

एक नजर

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन ने खटखटाया उच्चतम न्यायालय का दरवाजा

नई दिल्ली। झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन घोटाले के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तारी के बाद करीब तीन माह से न्यायिक हिंसा में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पारित करने में देरी का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए उन्नीस अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि शीघ्र सुनवाई के मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रशेखर वैदिक को विचार कर सकते हैं।

कांग्रेस ने आंध्र में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों के उम्मीदवार किये घोषित

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा की तीन और विधानसभा के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किये हैं। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए आज बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने राज्य की नरसिंहपुर सीट से के बी आर नायडू, राजगोपेट से एस के बशीर तथा चित्तूर से एम जगपति को उम्मीदवार बनाया है।

एआईआरएफ की कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के शताब्दी अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को एआईआरएफ कार्यसमिति की बैठक यहां मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर हॉल में आयोजित की गयी। बैठक में देश की सामाजिक, आर्थिक दशा, रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों और नयी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली, रेलवे में यूनियनों की मान्यता हेतु गुप्त मतदान एवं अन्य मांगों से संबंधित कई प्रस्ताव भी सर्व सममति से पास किए गए। कार्यसमिति की बैठक के उपरान्त अपराह्न दो बजे नयी दिल्ली अजमेरी गेट से कर्नल सिंह स्टेशन तक शताब्दी अधिवेशन की रैली निकाली गयी। रैली में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े नेताओं के अलावा रेलवे के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।

बेहतर कल के लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी: प्रधानमंत्री

मोदी ने छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बेहतर कल के लिए आज सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश किये जाने की जरूरत है। श्री मोदी ने बुधवार को यहां छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने आये प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि उनकी भागीदारी आपदा मोचन से संबंधित बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण मुद्दे पर वैश्विक चर्चा और निर्णयों को मजबूत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में गठन के बाद से आपदा मोचन गठबंधन ने प्रभावशाली ढंग से कार्य किया है और अब यह 39 देशों तथा 7 संगठनों का वैश्विक गठबंधन बन गया है। उन्होंने कहा, यह भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को गंभीर विषय बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्सर इनके अस्वर को आर्थिक नुकसान की दृष्टि से देखा जाता है लेकिन वास्तव में इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव लोगों, परिवारों और समुदायों पर पड़ता है जिसे मापा नहीं जा सकता।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, हमें बेहतर कल के लिए आज सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा के बाद के पुनर्निर्माण का हिस्सा होने के साथ-साथ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सुदृढ़ता के पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती और इनका विश्व में व्यापक प्रभाव होता है। उन्होंने कहा, समस्त विश्व सामूहिक रूप से सभी सुदृढ़ हो सकता है, जब प्रत्येक देश अपने आप में सुदृढ़ हो। उन्होंने साझा जोखिमों के कारण सबको सशक्त बनाये जाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सीडीआरआई तथा यह सम्मेलन पूरी दुनिया को इस सामूहिक मिशन के लिए एक साथ आने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, साझा रूप से



सशक्त होने के लिए, हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए। आपदाओं के बहुत अधिक जोखिम वाले छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसे 13 स्थानों पर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सीडीआरआई कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने डोमिनिका में प्रतिरोधी आवास, पापुआ न्यू गिनी में प्रतिरोधी परिवहन नेटवर्क और डोमिनिकन गणराज्य और फिजी में उन्नत प्रारंभिक

चेतावनी प्रणालियों का उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सीडीआरआई का फोकस ग्लोबल साइड पर भी है। श्री मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान चर्चा के केंद्र में वित्तपोषण सहित एक नए आपदा जोखिम कार्य समूह के गठन को याद किया और कहा कि इस तरह के कदम सीडीआरआई के विकास के साथ-साथ दुनिया को एक लचीले भविष्य की ओर ले जाएंगे।

रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जरूरी: जनरल पांडे

नई दिल्ली, एजेंसी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अनुसंधान एवं विकास के बल पर रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू प्लेटफार्मों तथा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत पर बल दिया है। जनरल पांडे ने बुधवार को यहां एक सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार का आयोजन सेना की ओर से सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज ने किया था।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के नए रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि सूचना से लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। हाल के संघर्षों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विघटनकारी और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है। इस तरह यह आधुनिक युद्धों के चरित्र को बदल रही है। जनरल पांडे ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को आधुनिक, चुस्त और प्रौद्योगिकी से लैस करने की दिशा में प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी हितधारकों, सेनाओं, उद्योग भागीदारों, स्टार्ट-अप, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा जगत और नीति



निर्माताओं से अपने प्रयासों में तालमेल बिटाने और एक जीवंत राष्ट्रीय रक्षा इको-सिस्टम विकसित करने का आग्रह किया। सेमिनार में सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत हार्डवेयर जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों तथा उद्योग जगत के पेशेवरों को एक मंच पर लाया गया। इसका उद्देश्य सेना में तकनीकी उन्नयन के लिए चल रही पहलों को तेज गति देने के उद्देश्य से शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें देश में रक्षा क्षेत्र की प्रगति और क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी का दस साल का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा: अमित शाह

संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार शाम को कहा कि नरेन्द्र मोदी को देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश संकल्पित है। गृहमंत्री महमूरगंज स्थित मोतीझील में वाराणसी लोकसभा के पांचों विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने काशी से पूरे पूर्वांचल में सियासी समीकरण साधते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रचंड जीत की जिम्मेदारी सौंपी और इसका मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि बाकी चिंता छोड़ कर बूथ को पकड़ कर हर बूथ में 300 वोट पार्टी के कार्यकर्ताओं को डलवाना है। हर लाभार्थी को पकड़ कर रखना है, काशी में हुए विकास को लोगों को बताना है, 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। इस संकल्प से सबको जोड़ना है। गृहमंत्री



ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 542 सांसदों में सबसे बेहतर है। किसी से उनका मुकाबला नहीं है। इतनी व्यस्तता के बावजूद सांसद बनने के बाद वे पचास बार काशी आए हैं। हर बार काशीवासियों के लिए सौगात लेकर आए हैं। युवाओं से लेकर 100 साल के वरिष्ठ नागरिक सबकी चिंता प्रधानमंत्री को है। गांव में रहने वाली गरीब माताओं से लेकर शहर के युवाओं के भविष्य व देश की सुरक्षा हर पहलू पर प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 30 साल से मैं विधायक और सांसद रहा हूँ, लेकिन मेरे सिर पर कभी भी

नरेन्द्र मोदी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही। काशी के पिछले दस सालों में हुए विकास कार्यों को विस्तार से गिनाते हुए कहा कि मोदी ने काशी को गौरव दिलाने का कार्य किया है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी को आधुनिक नगरी बनाया। बाबा विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का जिक्र कर कहा कि करोड़ों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं। देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और परिवारवाद से देश को मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 2024 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जिन्होंने समग्र देश नहीं समग्र दुनिया में काशी का नाम उज्ज्वल किया है।

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिये 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज लॉन्च

अहमदाबाद, एजेंसी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिये गुजरात में नडियाद के पास भारतीय रेलवे की वडोदरा-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर 100 मीटर लंबाई का पहला स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जापानी विशेषज्ञता के साथ भारत मेक-इन-इंडिया विजन के तहत इंपास्ट्रकचर निर्माण के लिये अपनी स्वदेशी तकनीकी और भौतिक क्षमताओं का तेजी से उपयोग कर रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यह स्टील ब्रिज ऐसे ही उदाहरणों में से एक है। 1486 टन के इस स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात के भुज जिले में स्थित कार्यशाला में किया गया जो ब्रिज लॉन्चिंग साइट से लगभग 310 कि.मी. दूर है। लॉन्चिंग के लिये ब्रिज को ट्रेलरों द्वारा साइट पर ले जाया गया। साइट पर स्टील ब्रिज को अस्थायी ट्रेलर पर जमीन से 15.5 मीटर की ऊंचाई पर असेंबल किया गया। इसके बाद 63 मीटर लंबाई और लगभग 430 टन वजन की लॉन्चिंग नोज को मुख्य पुल असेंबली के साथ



जोड़ा गया। स्टील ब्रिज को हाई टेंशन स्ट्रैंड्स का उपयोग करके 180 टन की क्षमता वाले दो जैक के स्वचालित तंत्र के साथ खींचा गया। ब्रिज को सावधानीपूर्वक योजना और सटीकता के साथ भारतीय रेलवे लाइनों के पूर्ण यातायात और पावर ब्लॉक के चलते लांच किया गया। टेंशनकल पॉइंट्स में ब्रिज की लंबाई 100 मीटर, में ब्रिज का वजन 1486 टन, लॉन्चिंग नोज की लंबाई 63 मीटर, लॉन्चिंग नोज का वजन 430 टन, स्टील के प्रत्येक उत्पादन बैच का मैनुफैक्चरिंग परिसर में अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा परीक्षण किया गया। स्टील ब्रिज

का निर्माण जापानी इंजीनियर द्वारा तैयार डिजाइन ड्राइंग्स के अनुसार कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग के उच्च तकनीक और सटीक संचालन द्वारा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को अंतरराष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित वेल्डर और पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्यशाला में, वेल्डिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग, जापानी अंतरराष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञों द्वारा भी की जाती है। निर्मित स्टील स्ट्रक्चर चेक असेंबली प्रक्रिया से गुजरने के बाद पांच-परत तकनीक का उपयोग करके पेंट किया जाता है। स्टील गर्डर्स के लिये हिस्सों को जोड़ने का काम टोर शीयर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स (टीटीएचएसबी) का उपयोग करके किया जाता है, जिसका उपयोग भारत में किसी भी रेलवे परियोजना के लिये

पहली बार किया जा रहा है। यह स्टील ब्रिज, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए तैयार किये गये 28 स्टील पुलों में से दूसरा है। पहला स्टील ब्रिज गुजरात के सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर लॉन्च किया गया था। इन स्टील ब्रिज को बनाने में लगभग 70,000 टन निर्दिष्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। स्पैन की लंबाई 60 मीटर 'सिंपली सपोर्टेड' से लेकर 130 प्लस 100 मीटर 'कंटीन्यूअस स्पैन' तक होती है। 40 से 45 मीटर तक वाले प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज के विपरीत, स्टील ब्रिज राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिये सबसे उपयुक्त होते हैं, जो नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिये उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 कि.मी. प्रति घंटे के बीच चलने वाली भारी दुलाई और अर्ध उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। अब, स्टील गर्डर्स के निर्माण में समान विशेषज्ञता एमएचएसआर कॉरिडोर पर भी लागू की जायेगी, जिसमें 320 कि.मी. प्रति घंटे की परिचालन गति होगी।

नरेन्द्र मोदी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर गरीबों का हक मारा: राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रूपए का कर्ज माफ कर गरीबों का हक छीना है।

श्री गांधी ने यहां जारी एक बयान में आज कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अरबपति मित्रों का 1,60,00,00,00,00,000 मतलब 16 लाख करोड़ रूपया कर्ज माफ किया है। उनका कहना था कि इतनी रकम का कर्ज माफ कर श्री मोदी ने देश के करोड़ों गरीबों के हक को छीने का काम किया है। उन्होंने कहा इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को एक लाख रुपये साल की नौकरी मिल सकती थी और 16 करोड़ महिलाओं को एक लाख रुपये साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी



बदली जा सकती थी तथा 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। श्री गांधी ने कहा कि इतनी रकम से पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रु में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था और तीन साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था इसके साथ ही दलित, आदिवासी और पिछड़े

समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। उन्होंने कहा जो पैसा 'हिंदुस्तानियों' के दर्द की दवा बन सकता था, उसे 'अडानियों' की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। देश नरेन्द्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस हर हिंदुस्तानी को प्रगति के लिए सरकार चलाएगी।

मतदाता की बेरुखी लोकतंत्र के लिए नहीं हैं अच्छे संकेत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता ने निराश ही किया है। आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर कम होना निश्चित रूप से किसी भी रूप में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना निश्चित रूप से सोचने को मजबूर कर देता है। चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो साफ हो जाता है कि 2019 की तुलना में दो प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। हालांकि त्रिपुरा और सिक्किम में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत को छूने में सफल रहा है पर वहां भी 2019 की तुलना में कम है। त्रिपुरा में 2019 के 81.9 प्रतिशत की तुलना में 81.5 प्रतिशत और सिक्किम में 84.8 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिशत मतदान रहा है। पहले चरण के चुनावों में मतदान का सबसे कम प्रतिशत बिहार का रहा है जहां मतदान का आंकड़ा 50 प्रतिशत को भी छू नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में अवश्य 2019 की तुलना में एक प्रतिशत से कुछ अधिक मतदान रहा है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है 12 सीटों पर हुए मतदान में मतदान प्रतिशत में 6 फीसदी की गिरावट रही है। सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में कम रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों आंशिक सूचना के आधार पर है पर इनमें कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले चरण में लोकसभा की 543 सीटों में से 20 प्रतिशत से कुछ कम 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। यदि मतदाताओं का अगले चार चरणों के मतदान में भी यही रुख रहता है तो यह चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैरसरकारी संगठनों सहित सभी के लिए चिंतनीय हो जाता है।

मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया है वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है। आज मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक मतदान केन्द्र पर एक सीमा तक ही मतदाता होने के साथ ही मतदान केन्द्र पर सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता क्रमांक से लेकर मतदान केन्द्र तक की जानकारी का समावेश करते हुए परची उपलब्ध कराई जाती है। सीनियर सिटिजन और मतदान केन्द्र तक जाने में अक्षम मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। मतदाताओं को जागृत करने के लिए प्रचार के सभी माध्यम यहां तक कि सोशल मीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। मतदान को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए संपूर्ण व्यवस्था चाक चोबंद की जाती है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यहां तक कि उम्मीदवार से संबंधित



जानकारी साझा की जाती है। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान केन्द्र पर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि साक्षरता और लोगों में जागरूकता आई है। चुनाव आयोग के अलग अलग ऑब्जरवर द्वारा पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी गलत तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सके। इस सबके बावजूद मतदान कम होना गंभीर हो जाता है। लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में 44.87 प्रतिशत मतदान रहा था जो सर्वाधिक 67.40 प्रतिशत 2019 के 17 वीं लोकसभा के चुनाव में रहा। मतदान में उतार चढ़ाव तो देखा जाता रहा है पर चुनाव व्यवस्था के सरलीकरण, पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव की चाकचोबंद व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में साक्षरता में बढ़ोतरी के बावजूद यदि मतदान प्रतिशत 90 के आंकड़ों को भी नहीं छूता है तो यह घोर निराशाजनक है। हालांकि आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान

1984 के 64.01 के आंकड़ों को 2014 में पीछे छोड़ा गया पर 2019 के पहले चरण के मतदान से निराशा ही हाथ लगी है। आखिर शिक्षित मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इतना गैरजिम्मेदार नहीं नकारा जा सकता कि देश के नागरिक का भी अपने देश के प्रति लोकतंत्र के प्रति दायित्व होता है। आखिर हम सरकार की आलोचना करने में तो पीछे नहीं रहते पर कभी हमने सोचा है क्या कि हम मताधिकार का उपयोग करने के अपने दायित्व को नहीं समझ पाते हैं। अपनी सरकार चुनने के अवसर पर हम हमारे दायित्व को कैसे भूल जाते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी अपने आप में गंभीर हो जाती है। भारत जैसे देश के आम नागरिकों द्वारा इस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाना किसी अपराध से कम नहीं माना जाना चाहिए। हमें गर्व होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर हमें उस समय नीचे देखने को भी

मजबूर होना पड़ता है जब इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व पर आमनागरिक अपने दायित्व को समझने और उसे पूरा करने की भूल कर बैठता है और मताधिकार का उपयोग नहीं कर व्यवस्था को ठेंगा बताने का प्रयास करते हैं। मेरा तो यहां तक मानना है कि नोटा का प्रयोग भी सही विकल्प नहीं है वहीं मतदान का बहिष्कार तो देशद्रोह से कम अपराध नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार गैरसरकारी संगठनों और समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचना होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी आहुति देने के काम से मुहं मोड़ने वालों के प्रति कोई सख्त कदम जैसा प्रावधान होना ही चाहिए। कोई ना कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए ताकि लोग मतदान के प्रति संवेदनशील हो और मतदान अवश्य करें। यह समूची व्यवस्था को ही सोचने को मजबूर कर देता है। आने वाले चार चरणों में होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाता हिस्सा ले इसके लिए सभी स्तर पर समर्पित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

यूएनएफपीसीसीसी मानता है कि जलवायु परिवर्तन के कारकों को धामने, उत्सर्जन घटाने और प्रभावों को कम करने में विकसित मुल्कों के पास अधिक क्षमता है, इसे 'सामान्य किंतु अंतर लाने वाली जिम्मेवारी' नामक सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। पेरिस संधि-2015 के ध्येयों पर अमल फिलहाल शोचनीय रूप से बहुत कम है, जिसके अंतर्गत वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी स्वीकार्य सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर बनाए रखना है। लेकिन यह न होने पर, वास्तविक धरातल पर इसके प्रभाव स्वरूप मौसम में तीव्र बदलाव बढ़ते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में, तयोंकि पर्यावरणीय बदलाव भारत पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं और अधिकांशतः इसके पीछे जिम्मेवार विकसित देशों के कारनामे हैं, वया एक आम नागरिक इस जलवायु परिवर्तन से आजादी का हक पाने का दावा कर सकता है? तर्क के आधार कर कहे तो समस्या का मुख्य जिम्मेवार विकसित देशों का समूह है। अब तक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन संधियां विकासशील राष्ट्रों को सुधारक उपाय अपनाने के हेतु बहुत कम धन उपलब्ध करा पाई हैं। इसलिए, तो वया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अर्थ है कि लागत चाहे कितनी भी हो, भारतीय सरकार को पर्यावरण में सुधार के उपाय करने ही होंगे? इस अधिकार की अन्य अवधारणा है स्वतंत्रता का अधिकार बनाम भलाई का अधिकार। जीवन का अधिकार, अनिवार्यता की आजादी इत्यादि स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। शिक्षा का अधिकार, जलवायु परिवर्तन से निजात के अधिकार सहित साफ-सुथरा पर्यावरण पाने के हक को भलाई अधिकारों में गिना जाता है।

जलवायु संकट से जीवन रक्षा का अधिकार

प्रोदिमो घोष

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं आजादी की सुरक्षा) के दायरे को विस्तार देते हुए स्वतंत्रता के अधिकार या जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से सुरक्षा की आजादी को मान्यता दी है। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट हो कि आखिर 'अधिकार' का अर्थ क्या है। 'अधिकार' किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया वह दावा है (जैसे कि महिला, एलजीबीटीक्यूआईए इत्यादि) जिसकी अहमियत इसकी कीमतों और फायदों से कहीं ऊपर होती है। उदाहरणार्थ, एक पुलिसकर्मी यह दलील नहीं दे सकता कि किसी विधवा के यहां हुई चोरी को सुलझाने में जो वक और पैसा लगेगा यदि वह चोरी हुए माल या धन से अधिक है तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने का क्या औचित्य। दूसरा, अधिकार में सामान्यतः फर्ज भी निहित होता है किसी व्यक्ति, संस्थान अथवा सरकार काड़ ताकि दावा सही लगे। विभिन्न गैसों के वैश्विक उत्सर्जन, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, इनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे प्रभाव का विकासशील मुल्कों के अपने उत्सर्जन से संबंध कम ही है। इनकी सरकारें अपने तौर पर वैश्विक स्तर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने में कुछ अधिक नहीं कर सकतीं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति की जरूरत है, इस दिशा में अपेक्षित चाल 1992 से ही धीमी है, जब संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफपीसीसीसी) नामक प्रस्ताव अपनाया गया था।

यूएनएफपीसीसीसी मानता है कि जलवायु परिवर्तन के कारकों को धामने, उत्सर्जन घटाने और प्रभावों को कम करने में विकसित मुल्कों के पास अधिक क्षमता है, इसे 'सामान्य किंतु अंतर लाने वाली जिम्मेवारी' नामक सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। पेरिस संधि-2015 के ध्येयों पर अमल फिलहाल शोचनीय रूप से बहुत कम है, जिसके अंतर्गत वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी स्वीकार्य सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस से आजादी का हक पाने का दावा कर सकता है? तर्क के आधार कर कहे तो समस्या का मुख्य जिम्मेवार विकसित देशों का समूह है। अब तक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन संधियां विकासशील राष्ट्रों को सुधारक उपाय अपनाने के हेतु बहुत कम धन उपलब्ध करा पाई हैं। इसलिए, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अर्थ है कि लागत चाहे कितनी भी हो, भारतीय सरकार को पर्यावरण में सुधार के उपाय करने ही होंगे? इस अधिकार की अन्य अवधारणा है स्वतंत्रता का अधिकार बनाम भलाई का अधिकार। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी इत्यादि स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। शिक्षा का अधिकार, जलवायु परिवर्तन से निजात के अधिकार सहित साफ-सुथरा पर्यावरण पाने के हक को भलाई अधिकारों में गिना जाता है। स्वतंत्रता अधिकार में केवल जरूरत है अन्य कोई इनका उल्लंघन न करने पाए जबकि भलाई अधिकार वह है जिसकी प्राप्ति करने में तत्परता कर्तव्यों पर उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की जरूरत होती है। स्वतंत्रता अधिकारों को लागू



करने में अधिकांशतः बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगती। लेकिन, कल्याण अधिकारों को मूर्त रूप देने में सामान्यतः बहुत बड़े स्तर पर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। किंतु जब संसाधन पहले से कम पड़ते हैं, जैसा कि विकासशील मुल्कों में होता है, तब चुनाव करते वक्त विभिन्न अन्य कल्याण अधिकारों को तरजीह देनी पड़ती है। लेकिन इस किस्म के संसाधन मिलने की संभावना बहुत क्षीण है। वर्ष 2005 में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त धन से पर्यावरण संबंधित प्रभावों पर एक अध्ययन हुआ था। इसके उद्देश्यों में योजनाएं एवं निवारण कार्यक्रम का सुझाव देने के अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बनी स्थिति में राहत उपाय (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, वानिकी, चक्रवात शरणस्थली) की शिनाखा करना और उन पर होने वाले खर्च का अनुमान देना था। इसके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8 प्रतिशत इस किस्म के कार्यक्रमों के ऊपर खर्च हुआ था, यह व्यय भारत के रक्षा बजट जितना था। हो सकता है बाद में यह मात्रा और बढ़ गई हो। अतएव, क्या जलवायु परिवर्तन से आजादी का सुझाव है कि इन दोनों व्यावहारिकता में काफी उलझने हैं? साफ तौर पर, बाहरी स्रोतों का प्रभाव, यदि कोई है, तो वह बहुत कम होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जोषिम कम करने में होने वाले खर्च के ऐतिहासिक स्तर के मदेनजर लगता नहीं कि जलवायु परिवर्तन अधिकार को मूर्त रूप

देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अंश में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश है। तथापि, जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, समस्त संसाधनों का स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही, नागरिकों की आय बढ़ने पर, वे जलवायु प्रभाव के परिणामों से बचने को निजी तौर पर अधिक खर्च कर पाएंगे, मसलन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च, जल-संचयन और अतिशयी आपदाओं के संदर्भ में बीमा करवाना इत्यादि। कुल मिलाकर, जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी वैसे-वैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से नागरिकों का जोषिम कम होता जाएगा। इस असर से मुक्ति पाने में विकास एक चाबी है। कदाचित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य आशय जलवायु संबंधी जोषिमों से बचाव करने पर खर्च में कटौती को भावी संभावना को खत्म करना है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उस याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें राजस्थान और गुजरात में संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बर्टर्ड (तिलोली) पक्षी के अभयारण्य स्थल से होकर गुजरने वाली अक्षय ऊर्जा की बिजली तारों को जमीन के नीचे डालने का फैसला देने के खिलाफ अपील लगाई गई थी। ऊंचे खम्भों के माध्यम से लगी बिजली आपूर्ति तारों से टकरा कर बड़ी संख्या में पक्षी मारे जाते हैं। बिजली कंपनियों की दलील है कि इसमें बहुत खर्च आएगा और अक्षय ऊर्जा की दरें प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहेंगी। साफ है, जलवायु सततता का अधिकार और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने में भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी का निर्वहन इस मामले में परस्पर विरोधाभासी है। इस अक्षय ऊर्जा की परियोजना की क्षति से भारत को पेरिस जलवायु संधि में किए वादे को निभाना और मुश्किल हो जाएगा। और यदि इस योजना को जारी रखें तो संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति को बचना कठिन हो जाएगा। अदालत का सुझाव है कि इन दोनों चिंताओं का व्यावहारिक हल निकालने के लिए विशेषज्ञ अध्ययन करवाया जाए। यदि रास्ता निकलता है तो बहुत बढ़िया वार्ना शापद नीति अनुसंधान संस्थान इस मुश्किल दुविधा का हल निकालने में मददगार हो पाए।

विचार

मगर गरीबी है कि हटती ही नहीं गरीबी हटाओ का जुमला

राकेश गांधी

चुनाव आते ही गरीबों के चेहरे कुछ समय के लिए प्रसन्नता से खिल उठते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा पांच साल बाद उन्हें याद जरूर कर लिया जाता है। चुनाव के तत्काल बाद ये गरीब राजनीतिक दलों के नेताओं के मानस पटल से हट भी जाते हैं। याद आना अच्छी बात है, पर हैरानी इस बात की भी है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी आखिर गरीबी मिट क्यों नहीं रही..? क्यों राजनीतिक दलों ने 'गरीबी हटाओ' नारे को अपना स्थाई जुमला बना रखा है? गरीबी तो हटती नहीं, पर साल-दर-साल गरीबों का गरीबी में ही जरूर नामोनिशां मिट जाता है। चुनावी समर चल रहा है। अभी तो इन 'गरीबों' की भी पौ बारह है। नेता रोज ही इनकी पूजा-अर्चना व भरपेट खाना पहुंचाने में व्यस्त चल रहे हैं। चुनाव से निपटते ही इन गरीबों को फिर से इन्होंने के हाल छोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर मुफ्तखोरी की आदत डालकर इन गरीबों को गरीब ही बनाए रखने और सालो-साल इन पर राज करने का सिलसिला बरकरार जारी है। हाल ही में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी हुए हैं। जोर-शोर से आगामी पांच साल में गरीबों के भूखे पेट का उपचार करने की बात की जा रही है। इससे ज्यादा तो कुछ होगा भी नहीं। जब साढ़े सात दशक में भी नहीं हो पाया तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है। केवल गरीबी हटाने ही नहीं, हर बार लाखों नौकरियां देने के वादे भी किए जाते रहे हैं। ये बात अलग है कि पांच साल बाद भी हालात जस के तस ही रहते हैं और फिर शुरू हो जाता है जुमलों का दौर। इससे भी दुःखद तो ये है कि आजादी के बाद से लोगों को पानी, बिजली, सड़क, उच्च शिक्षा व बेहतरीन चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाने के भी वादे किए जाते रहे हैं। इसके उलट आजादी के 77 साल बाद भी देश में ऐसे कई शहर व गांव मिल जाएंगे, जहां डामर की सड़क तो छोड़ो, अभी कच्ची सड़क तक नसीब नहीं हुई है। घंटिया सीवरेज व्यवस्था के कारण बरसात के दिनों में शहरों में लोग कई-कई दिनों तक पानी से घिरे घरों में कैद रहते हैं। पीने को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। कई गांवों में यातायात के साधन तक नहीं पहुंच पाए हैं। देश की सिलिकॉन सिटी बंगलुरु जैसे प्रमुख शहर के लोग जब पेयजल संकट के भयानक हालात से जूझ रहे हैं तो दूरदराज के गांवों की क्या बात करें। हां, पिछले कुछ सालों में सारे देश में हाई-वे जरूर बने हैं। लिंक रोड से लोगों का आवागमन सुगम हुआ है। पर इसमें भी गरीब तो अभी भी गरीब ही है। उसकी गरीबी का निवारण अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। इसमें किसी एक राजनीतिक दल को दोष देने से कुछ होना भी नहीं है। देश में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। सालों-साल झूठे वादे करने वालों से बचने की जरूरत है। वैसे भी देश में किसी नागरिक को 'गरीब' कहना किसी गाली से कम नहीं है। गरीब का मतलब केवल निर्धन ही नहीं, बल्कि उन्हें जबरन दरिद्र, कंगाल, दीनहीन, बेचारा, लाचार जैसे शब्दों से नवाजना है। ऐसे में वे जरूरतमंद जरूर हो सकते हैं, पर 'गरीब' तो बिल्कुल नहीं। हमें ये मान लेना चाहिए कि अब देश में जब तक आखिरी इंसांन तक रोजगार, पर्याप्त पेयजल, बिजली, जरूरी चिकित्सा व शिक्षा के संसाधन नहीं पहुंच जाते, तब तक विकास की बात करना बेमानी होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि विख्यात सर्वोदयी व सामाजिक कार्यकर्ता तथा महात्मा गांधी के अनुयायी बाबा विनोबा जीवनपर्यन्त 'अन्त्योदय' की बात करते थे। 'अन्त्योदय' यानी अंत तक उदय। देश के आखिरी आदमी तक विकास की बात उनके इस ब्रह्मवाक्य में निहित थी। अन्त्योदय आज देश की अहम जरूरत बन गया है। सरकार जब तक इस 'अन्त्योदय' को नहीं अपनाती, तब तक देश को विकसित राष्ट्र नहीं माना जा सकता।



एक नजर

रुसी उप रक्षा मंत्री को रिश्वात के आरोप में हिरासत में लिया गया



मॉस्को, एप्रैल 25। रुसी जांच समिति ने बताया कि रूस के उप रक्षा मंत्री तिमूर इवानोव को बड़े पैमाने पर रिश्वात लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। रुसी जांच समिति ने टेलीग्राम पर कहा, रूसी संघ के उप रक्षा मंत्री तिमूर इवानोव को अपराधिक संहिता के अनुच्छेद 290 के भाग 6 (रिश्वात लेने) के तहत अपराध करने के संदेह में हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, मामले में जरूरी जांच कार्रवाई की जा रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि इवानोव की हिरासत के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सूचित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी तास (टीएसएस) के अनुसार, इवानोव को मई 2016 में उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। इस पद पर वह सशस्त्र बलों के लिए संपत्ति प्रबंधन, सेना की तैनाती, आवास और चिकित्सा सहायता के आयोजन के साथ-साथ राज्य रक्षा आदेश के तहत खरीद को देखरेख के प्रभारी थे।

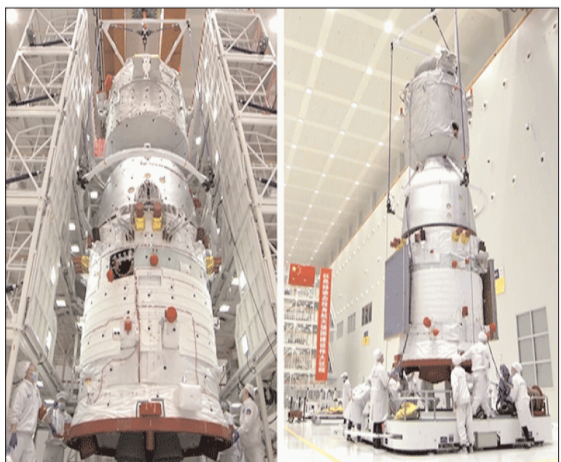
यूक्रेन ने व्यवसायों, उद्योग पर बिजली आपूर्ति प्रतिबंध लगाया

कीव, एप्रैल 25। यूक्रेन की सरकारी एनर्जी कंपनी उक्रेनर्नो ने कहा है कि वह रूसी मिसाइल हमलों के कारण हुई बिजली की कमी के कारण व्यवसायों और उद्योग पर बिजली आपूर्ति प्रतिबंध लगाएगी। उक्रेनर्नो ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेशन कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण बुनियादी



सुविधाओं और रक्षा उद्यमों को प्रभावित नहीं करेगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य यूक्रेन के क्रिवी रिह जिले में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति प्रतिबंध चौबीसों घंटे लागू रहेगा। इसके अलावा, बिजली कटौती से पूर्वी खार्किव क्षेत्र में निजी घर प्रभावित होंगे। उक्रेनर्नो के अनुसार, एनर्जी (ऊर्जा) घाटे को पूरा करने के लिए यूक्रेन लगातार दूसरे दिन यूरोप से बिजली आयात कर रहा है। पिछले हफ्ते, यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल ने कहा था कि रूसी हमलों के कारण यूक्रेन ने हाल के महीनों में अपनी 8 गीगावॉट से अधिक क्षमता खो दी है।

अंतरिक्ष यान शेनझोउ-18 चालक दल के साथ 25 अप्रैल को होगा प्रक्षेपित



जिउऊान, एप्रैल 25। उत्तर पश्चिमी चीन में जिउऊान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष यान शेनझोउ-18 चालक दल के साथ बीजिंग समय के अनुसार गुरुवार को रात 8:59 बजे प्रक्षेपित किया जायेगा। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी (सीएमएसए) ने बुधवार को इसकी घोषणा की। सीएमएसए के उप निदेशक लिन जिकियांग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंतरिक्ष यान शेनझोउ-18 अंतरिक्ष उड़ान मिशन को पूरा करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों - ये गुआंगफू, ली कांग और ली गुआंगसु - को ले जाएगा और श्री ये इसके कमांडर होंगे। शेनझोउ-18 चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का 32वां उड़ान मिशन है और चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास चरण के दौरान तीसरा मानवयुक्त मिशन है। चालक दल लगभग छह महीने तक कक्षा में रहेगा और उनका इस साल अक्टूबर के अंत में उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर लौटने का कार्यक्रम है। लिन ने कहा प्रक्षेपण में लॉन्च मार्च-2एफ वाहक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, जो जल्द ही प्रणोदक से भर जाएगा। लिन ने कहा, शेनझोउ-18 चालक दल को कक्षा में काम सौंपने के बाद शेनझोउ-17 चालक दल 30 अप्रैल को डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर लौटने वाला है।

अलास्का में विमान नदी में गिरा

सेन फ्रांसिस्को। अमेरिका में अलास्का राज्य के फेयरबैंक्स में मंगलवार को एक डगलस डीसी-4 हवाई जहाज नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, फेयरबैंक्स में तानाना नदी के क्षेत्र में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के बाद वहां बचाव और राहत कार्य जोरशोर से चलाया जा रहा है। नेशनल ट्रॉसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अलास्का प्रमुख क्लिंट जॉनसन ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जब डगलस डीसी-4 फेयरबैंक्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण में प्रस्थान करने के तुरंत बाद सुबह 10:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस पर कितने लोग सवार थे। हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा, हम कलेनबर्ग रोड के पास तानाना नदी पर डगलस डीसी-4 विमान से जुड़ी मौजूदा स्थिति को स्वीकार करते हैं। अलास्का स्टेट ट्रूपर्स सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं और हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। फेयरबैंक्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने जनता से इस क्षेत्र से बचने का आग्रह किया।

ईरान के साथ कारोबार पर प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में भी सजग रहें- अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कारोबार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के जोखिम की भी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की यात्रा के बारे में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा, 90%में व्यापक तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। ईरान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान ने आठ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में उसकी मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें चीन की तीन कंपनी भी शामिल हैं। पटेल ने कहा, प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों के उत्पादन और उनके प्रसार को बढ़ावा दे रही थीं। ये बेलासूस में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़ी कंपनी हैं और हमने देखा है कि



इन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जरूरी घटक और अन्य सामान मुहैया कराए। एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में

पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं। राइडर ने कहा, वह क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार है।

इमरान की पार्टी ने पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के साथ गुप्त बातचीत की बात से इनकार किया

इस्लामाबाद। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान-नीत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने देश की शक्तिशाली सेना के साथ गुप्त बातचीत की किसी भी अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि पार्टी को किसी संस्था के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। पीटीआई प्रमुख बेरिस्टर गौहर खान ने रावलपिंडी में अड्डियाला जेल के बाहर संवाददाताओं से कहा, 90%आज, मैंने पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान से पूछा कि क्या कुछ संस्थानों ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया है। इमरान खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। गौहर खान के हवाले से डॉन समाचार पत्र की एक खबर के अनुसार, उन्होंने

कहा कि किसी ने भी बातचीत के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है और न ही उन्हें किसी से बातचीत के लिए कोई संदेश मिला है। इससे पहले मीडिया के एक तबके में खबर आयी थी कि इमरान ने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता अब भी प्रतिष्ठान (सेना) के संपर्क में हैं। उसके कुछ दिनों बाद गौहर खान ने यह स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा, अन्य पार्टी के नेतृत्व का भी यही हाल है। अगर हमें बातचीत के लिए किसी से भी कोई संदेश मिलता है तो हम मीडिया को सूचित करेंगे। गौहर खान ने स्पष्ट किया कि पीटीआई की जब भी संवाद में रुचि होगी, तो यह खुले तौर पर आयोजित होगी और मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी।

ईरानी राष्ट्रपति रईसी का पाकिस्तान दौरा संपन्न

इस्लामाबाद। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा संपन्न हो गया है। इस दौरान उन्होंने देश के प्रमुख नेताओं के साथ 90%लाभदायक बातचीत की और व्यापार-ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। आठ फरवरी के आम चुनाव के बाद किसी राष्ट्रीयक का यह पहला पाकिस्तानी दौरा था। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने अपने समकक्ष आसिफ अली ज़रदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक और सिंध एवं



दोनों पक्षों में सहमति बनी। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, रईसी ने अपनी पत्नी और एक उच्च स्तरीय टीम के साथ लाहौर और कराची का भी दौरा किया, जिसमें विदेश मंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल था।

दशकों में सबसे गंभीर खतरों का सामना कर रहे वैश्विक मानवाधिकार- एमनेस्टी

लंदन, एप्रैल 25। लंदन स्थित समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में मानवाधिकार दशकों में सबसे गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने गाजा और यूक्रेन में संघर्ष के साथ-साथ सत्तावादी सरकारों पर कहा कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मौलिक अधिकारों को उपेक्षा कर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एमनेस्टी के महासचिव एनेस कैलमार्ड ने कहा, गाजा में नरसंहार को रोकने में उनके सहयोगियों की विफलता के चलते इजरायल लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून को उपेक्षा कर रहा है। यूक्रेन पर रूस का आक्रामक, विश्व में सशस्त्र संघर्ष की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा गया है। उदाहरण के लिए, सूडान, इथियोपिया और म्यांमार में वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था के खत्म होने का उल्लंघन है। कैलमार्ड ने कहा, 2023 में हमने जो देखा वह पुष्टि करता है कि कई शक्तिशाली देश मानव अधिकारों की घोषणा में निहित मानवता और सार्वभौमिकता के



संस्थापक मूल्यों को त्याग रहे हैं। अन्य बातों के अलावा, रिपोर्ट गाजा युद्धविराम के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महीनों तक बाधित करने के लिए अमेरिका द्वारा अपने वीटो के इस्तेमाल की आलोचना करती है। एक प्रेस विज्ञप्ति में एमनेस्टी ने कहा, रिपोर्ट ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के विचित्र दोहरे मानकों को भी उजागर करती है, रूस और हमस द्वारा युद्ध अपराधों के बारे में उनके सुस्थापित विरोध को देखते हुए, साथ ही वे इस संघर्ष में इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। वैश्विक

चर्च में चाकूबाजी घटना के बाद छापे में सात नाबालिग गिरफ्तार

सिडनी, एप्रैल 25। सिडनी के वेकले चर्च में पादरी को चाकू मारने के मामले के बाद बुधवार को एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया जिसमें पूरे सिडनी में सात नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) की डिप्टी कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी नाबालिग हैं, और अन्य पांच हमारी पृष्ठताल में पुलिस की सहायता कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, वेकले चाकूबाजी मामले पर हमारी जेसीटीटी (संयुक्त काउंटर टेररिज्म टीम) जांच कर रही है। इस कड़ी में, हमने कथित अपराधी और उसके कुछ साथियों के नेटवर्क के बीच संबंधों की पहचान की है, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे हिंसक विचारधारा वाले हैं। ऑपरेशन स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11:15 बजे शुरू हुआ, जिसमें एएफपी और न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स (एनएसडब्ल्यूपीएफ) के 400 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। दक्षिण-पश्चिमी सिडनी में कुल 13 तलाशी वारंट एजिक्यूट



किए गए हैं। एनएसडब्ल्यूपीएफ के डिप्टी कमिश्नर डेविड हडसन ने कहा कि 16 वर्षीय अपराधी को गिरफ्तारी के बाद कई सहयोगियों की पहचान की गई, जिन पर और अधिक ध्यान देने और जांच की आवश्यकता है। हडसन ने कहा, ये धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथी विचारधारा वाला हैं। घटना के बाद से ये जांच आगे बढ़ रही है। जांच में व्यापक निगरानी गतिविधियां और उन व्यक्तियों की गहन जांच शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वे सभी एक-दूसरे को जानते हैं,

कुछ तो काफी करीब से जानते हैं, सभी का एक ही मकसद था। 15 अप्रैल को, स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 7:10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सिडनी के वेकली चर्च में पादरी को चाकू मारा गया है। 53 वर्षीय पादरी को सिर पर गंभीर चोटें आयी थी। एक 16 वर्षीय नाबालिग को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आतंकवादी घटना में शामिल होने का आरोप है। इस अपराध के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

गाजा युद्धविराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करेगा कतर

दोहा, 24 अप्रैल (वेब वार्ता)। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि कतर, इजरायल और हमस के बीच मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। माजिद अली-अंसारी ने मंगलवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और अधिकारियों का मकसद मध्यस्थ के रूप में कतर की भूमिका पर हमला करना था। वे ऐसे हमलों को सही ठहराने के लिए गलत जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कतर को कुछ इजरायली और अमेरिकी राजनेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने खाड़ी देश पर आतंकवादी संगठन के बहुत करीब होने का आरोप लगाया है। संघर्ष की शुरुआत के बाद से दोहा ने बार-बार आरोपों को खारिज किया है। गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के मकसद से इजरायल और हमस के बीच बातचीत में गतिरोध आ गया है। प्रवक्ता ने कहा, हम यह देखेंगे कि क्या दोनों पक्षों की स्थिति में कोई बदलाव आया है जिससे बातचीत आगे बढ़े। 17 अक्टूबर 2023 को इजरायल-हमस संघर्ष शुरू होने के बाद से कतर दोनों युद्धरत पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है।

चीन ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए नए साझेदारों की घोषणा की

वुहान। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) ने बुधवार को घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (आईएलआरएस) के निर्माण और संचालन में एक देश और अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित अधिक भागीदार भाग लेंगे। चीन द्वारा शुरू किए गए आईएलआरएस कार्यक्रम को इस नवीनतम प्रगति का खुलासा मध्य चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में चीन के अंतरिक्ष दिवस के शुभारंभ समारोह में किया गया। आईएलआरएस के नए साझेदारों में निकारागुआ, एशिया-प्रशांत अंतरिक्ष



सहयोग संगठन तथा अरब संघ खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान शामिल हैं। सीएनएसए के अनुसार, चीन आईएलआरएस से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इन तीन पक्षों के साथ सहयोग करेगा, जिसमें इसके प्रदर्शन, इंजीनियरिंग कार्यान्वयन, संचालन और प्रयोग शामिल हैं। सीएनएसए के अधिकारियों ने तीनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों के साथ आईएलआरएस पर सहयोग पर समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा, स्टेशन का बुनियादी मॉडल लगभग 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। सीएनएसए के अनुसार अनुसंधान स्टेशन अल्पकालिक मानवीय भागीदारी के साथ लंबी अवधि के लिए स्वायत्त रूप से संचालित होगा। चीन में 24 अप्रैल, 1970 को अंतरिक्ष में अपने पहले उपग्रह डोंगफेंगहोंग-1 के प्रक्षेपण के उपलक्ष में 24 अप्रैल को देश के अंतरिक्ष दिवस के रूप मनाया जाता है।

